International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709, Print ISSN: 2664-8695
Received: 07-05-2022, Accepted: 06-06-2022, Published: 21-06-2022
Volume 4, Issue 1, 2022, Page No. 50-52

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद

डॉ. पुष्पा देवांगन[1], डॉ. बलभद्र प्रसाद देवांगन[2]
[1] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, के. पी. महाविद्यालय, बंधापाली सारंगढ़, छत्तीसगढ़, भारत
[2] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, अशोका महाविद्यालय, उम्मेदपुर, सारंगढ, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
नक्सलवाद एक विचारात्मक, राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष है जो माओवाद एवं मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष पर आधारित है। वर्तमान समय में भी नक्सलवाद जैसी समस्या इसीलिए विद्यमान हैं क्योंकि पिछड़े एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकारी स्तर में ध्यान नहीं दिया जाता है तथा नक्सलवाद जैसी समस्या का समाधान पूर्ण रूप से सैनिक बल के द्वारा नहीं की जा सकती। आवश्यकता इस बात की है कि इन क्षेत्रों में शासन प्रशासन के जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन और स्थानीय लोगों के साथ तालमेल स्थापित करनी होगी तभी नक्सलवादी समस्या को दूर किया जा सकता है।

मुख्य शब्दः विचारात्मक, माओवाद, मार्क्सवाद, प्रशासन, नक्सलवाद, समाधान

नक्सलवाद एक विचारात्मक, राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष है जो माओवाद एवं मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष पर आधारित है। इसकी शुरूआत नक्सलबाडी आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाडी क्षेत्र से हुई। इसी कारण नक्सलबाडी गांव के नाम पर ही इस उपग्रंथी आंदोलन को नक्सलवाद कहा गया। नक्सलवादी आंदोलन का नेतृत्व चारू मजूमदार, कानू सान्याल एवं कन्हाई चटर्जी ने किसानों एवं आदिवासियों को सामंती शोषण के विरूद्ध पूंजीपतियों व भूपत्तियों के विरूद्ध सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समान्ता करने के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जन संग्राम की सहायता से अपना वर्चस्व स्थापित करना था।
नक्सलवादी आंदोलन में जन अदालत के माध्यम से चोरी, डकैती, दहेज के मामले, जमीन से संबंधित विवाद इत्यादि मामले की सुनवाई होती है। इसमें हत्या, अंग भंग, आर्थिक दण्ड, सिर मुण्डन इत्यादि सजा दिये जाते और लागू किये जाते हैं। युवाओं को आकर्षित करने के लिए प्रचार–प्रसार किया जाता है तथा कई विद्यालय चलाये जाते हैं, जिसमें क्रांतिकारी किताबें पढ़ाये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरूआत 1990 के दशक में हुआ है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी संगठन में सबसे ज्यादा प्रभाव M.C.C. का है। छत्तीसगढ़ में M.C.C.K. के अलावा TPC, PLFI, JPC, JSJMM, RCC इत्यादि हैं। छत्तीसगढ़ गठन के बाद से छोटी बड़ी लगभग हजारों नक्सली घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें आम लोगों पर हमले, हत्या, पुलिस थानों पर हमले, मुठभेड़, रेलवे स्टेशन को जलाना एवं रेल पटरी को उखाड़ना इत्यादि शामिल है।
भारत में कुल 25 जिलों को अति माओवाद प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 14 जिले शामिल है। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में – बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोण्डागांव, कांकेर, राजनांदगॉव, बालोद, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, कवर्धा एवं बलरामपुर हैं। इनका प्रशिक्षण पहाड़ों के पास या घने जंगलों के बीच किया जाता है।

नक्सलवाद के कारण

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों के मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। इन क्षेत्रों में पर्याप्त गरीबी होना, बेरोजगारी, अशिक्षा, भौगोलिक अवस्थिति, भूमि संबंधित विवाद, आजीविका संबंधी, विस्थापन एवं जबरन बेदखली, सामाजिक बहिष्करण, शासन संबंधी कारक, कमजोर न्याय प्रणाली के कारण नक्सली स्थानीय लोगों को बहला–फुसलाकर शामिल कर लेते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों के विकास के लिये उचित फंड दिया जाता है जिसका ईमानदारी पूर्वक खर्च नहीं किया जाता है। वहां के सरकारी अधिकारी एवं स्थानीय नेता चाहते हैं कि यह व्यवस्था बरकरार रहे क्योंकि प्रभावित क्षेत्रों में विकास के नाम पर आने वाले पैसे से उनके जेब भरते रहें। पैसों की इस बंदरबांट में नक्सली कमांडरों और सरकारी व्यक्तियों की मिली भगत होती है। गांव में संचार की सुविधा का अभाव नक्सलवाद में वृद्धि का एक प्रमुख कारण रहा है।

नक्सलीयों के आय के स्त्रोत

नक्सलियों के आय का मुख्य स्रोत कारखानों, खनिज खानों, बीड़ी पत्तों के ठेकेदारों, चिमनी भट्टा, प्रखंड स्तर के पदाधिकारियो से लेवी, अपहरण, प्रखण्ड के माध्यम से संचालित विकास योजनाओं के ठेकेदारों से मोटी रकम वसूलते है। राजकीय उच्च पद के निर्माण के अधिकारियों से ऊंची रकम वसूलते है एवं अपहरण से मनमाना पैसा वसूलते है।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का विकास

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विकास का कारण शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों के सामाजिक, आर्थिक प्रगति के लिए सरकार की पहुंच ना होना है। यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाये तो गरीबी और आर्थिक विषमता के चलते नक्सलवाद अपने चरम स्थिति पर है साथ ही साथ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खनिज संसाधन पर सरकारी और गैर–सरकार संस्थाओं द्वारा बिना नीति नियम के दोहन संबंधी कार्य जारी रहना हैं। हालांकि वर्तमान समय में नक्सल वादी संगठन का एक मात्र उद्देश्य लेवी वसूलना और सरकारी कार्यो में बाधा पहुंचाना है।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के प्रभाव

नक्सल प्रभावित क्षेत्र को रेड कोरिडोर ;त्मक ब्वततपकवतद्ध के प्रभाव से जाना जाता है जिसका अर्थ भारत के पूर्वी, मध्य और दक्षिण के वे भाग जहां नक्सलवाद की स्थिति काफी मजबूत है, उसे रेड कॉरिडोर कहा जाता है। जून, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 10 राज्यों में इसका विस्तार पाया गया है जिसमें छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना है। छत्तीसगढ़ में 14 जिला रेड कोरिडोर के अंतर्गत आता है जिसमे बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोण्डागांव, कांकेर, राजनांदगॉव, बालोद, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, कवर्धा, बलरामपुर आदि जिला प्रभाव में है।

वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का इतना अधिक प्रभाव है, जिसके कारण निम्न चुनौतियां देखने मिलती है :–

1. कानून एवं व्यवस्था के लिए समस्या।
2. सरकारी एवं निजी संपत्ति का भारी नुकसान।
3. अधिकारियों एवं नागरिकों की हत्या।
4. महिला और बच्चों को नक्सलवादी आंदोलन में जबरदस्ती शामिल करना।
5. आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि।
6. सामुहिक सौहार्दता में कर्मी
7. राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का खतरा।
8. राष्ट्र विरोधी शक्तियों का प्रोत्साहन।
9. संबंधित क्षेत्र का विकास प्रभावित होना।
10. देश की अंतराष्ट्रीय छवि का नुकसान।

नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाये कदम

- **नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगारमुखी कौशल विकास योजना (रौशनी) :** रोशनी का प्रारंभ आत्मसमर्पण करने वाली नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करने वाले को प्रोत्साहन राशि, जीवन बीमा, रोजगार, प्रशिक्षण, कृषि कार्यों के लिए भूमि, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध आदि सुविधायें सरकार द्वारा की जाती है।

- **समाधान** (SAMADHAN) **पहल**

  गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2017 में प्रारंभ किया गया। समाधान से तात्पर्य :

1. S – Smart Leadership.
2. A – Aggressive Strategy.
3. M – Motivation And Training.
4. A – Actionable intelligence.
5. D – Dashboard based key key performance indicators and key result area.
6. H – Harbessing technology.
7. A – Action plan for each threat.
8. N – NoAccess to financing.

छत्तीसगढ़ में प्रमुख अभियान/ऑपरेशन

1. **ऑपरेशन कॉम्ब** : छत्तीसगढ़ के कुछ रेलवे स्टेशनों पर लगातार हो रही डकैतियों पर रोक लगाने के लिए इस अभियान की शुरूआत की गई। यह अभियान छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
2. **ऑपरेशन अग्निदूत** : राज्य के बस्तर एवं सरगुजा तथा इससे सटे कुछ जिलों में बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन अग्निदूत अभियान शुरू किया गया था।
3. **ऑपरेशन जंगल** : राज्य के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, बलरामपुर एवं सरगुजा जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल अभियान शुरू किया गया था।
4. **ऑपरेशन K2** : नक्सलियों के विरूद्ध यह अभियान 2005 में छत्तीसगढ के साथ बिहार एवं झारखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाया गया था।

5. **ऑपरेशन नई दिशा** : राज्य सरकार द्वारा यह अभियान नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए चलाया गया था। सरकार इस योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नगद राशि के अलावा उनके पुनर्वास और सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करती है।
6. **ऑपरेशन ग्रीन हंट** : भारतीय अर्द्धसैनिक बलों द्वारा नक्सलियों की संगठन के खिलाफ शुरू किये गये अभियान को मीडिया संगठनों द्वारा ऑपरेशन ग्रीन हंट का नाम दिया गया। यह अभियान नवंबर 2009 से नक्सल प्रभावित 5 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उड़िसा में प्रारंभ किया गया।
7. छत्तीसगढ़ के जंगल में Operation Jal, Operation Anaconda- 1, 2 चलाया गया।
8. 2013 में नक्सलियों के धर–पकड़ के लिए Operation Khoj चलाया गया।
9. छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित जिले में Operation Octopus (2022) चलाया गया।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की वर्तमान स्थिति

छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को नक्सलमुक्त घोषित करने की तैयारी चल रही है जिनमें राजनांदगॉव, बालोद, कवर्धा, महासमुंद एवं धमतरी ये अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किये जायेंगे। वहीं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोण्डागांव, कांकेर, गरियाबंद एवं बलरामपुर फिलहाल नक्सलवाद प्रभावित जिले में शामिल रहेंगे। राज्य के 4 जिले कोण्डागांव, कांकेर, गरियाबंद एवं बलरामपुर में लगभग नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। आगे भी नक्सलियों के खिलाफ नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेंगे।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में भी नक्सलवाद जैसी समस्या इसीलिए विद्यमान है क्योंकि पिछड़े एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकारी स्तर में ध्यान नहीं दिया जाता है तथा नक्सलवाद जैसी समस्या का समाधान पूर्ण रूप से सैनिक बल के द्वारा नहीं की जा सकती है। आवश्यकता इस बात की हैं की इन क्षेत्रों में शासन प्रशासन के जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन और स्थानीय लोगों के साथ तालमेल स्थापित करनी होगी तभी नक्सलवादी समस्या को दूर किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. मोहती, मनोरंजन (1980), रिवोल्यूशनरी वाईलेन्स–ए स्टडी ऑफ माओइस्ट मूवमेंट इन इंडिया, नई दिल्ली, स्टेलिंग पब्लिशर्स।
2. राम, मोहन (1972), माओइसम इन इंडिया, विकास पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
3. जोहरी, जे.सी. (1972), नक्सलाइट पोलिटिक्स इन इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेन्ट्री स्टीडीह, रिसर्च पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. बनर्जी, सुभन्त (1980), इन द बैंक ऑफ नक्सलवाड़ी ए हिस्ट्री ऑफ दी नक्सलाइड्स मूवमेंट इन इंडिया, सुवर्णरेखा पब्लिशर्स, कलकत्ता।
5. घोष, शंकर (1974) द नक्सलाइट मूवमेंट, ए माओइस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ कर्नल के.एल. मुखोपाध्याय, सुवर्णरेखा पब्लिशर्स, कलकत्ता।
6. Aggarwal, P.K. (2010) Nexalism:Causes and cure, Manas Publication, New Delhi.
7. Ahluwalia, V.K. (2013) Reel Revolation 2020 and beyond: Strategic Challenges to Resolve Nexalism. Boolmsbury in India, New Delhi.
8. Banjerjee, Sumanta (2006) Nexlite – Through the Eyes of Police, Subarnarekha Publishers, Kolkata.
9. Chakravarti, Sudeep (2008) Red Sun Travels in 20th Century, Offset Printer, Delhi.
10. Ramchandran, Sudha (2010) The Moist conflict in Dandakaranya Centre for Security Analysis, Chennai.
11. Raman, P.V. (2008) State Response to Moist challenge: an Overview, National book Trust, New Delhi.